

## कृषि विभाग

दिनांक 2 मार्च, 2009

**संख्या 589-कृषि II (1)-2009/2596.**—हरियाणा के राज्यपाल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वांछित विस्तृत जिला कृषि योजना इकाई में अनुसंधान एवं विस्तार के बीच अन्तर का पता लगाने व रूपरेखा तैयार करने व इनमें संसर्ग स्थापित करने के लिये कृषि समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु निम्नलिखित को सम्मिलित करके एक जिला कृषि योजना इकाई का गठन करते हैं :—

1. अध्यक्ष जिला परिषद् ,	अध्यक्ष
2. उपायुक्त	उपाध्यक्ष
3. जिला परिषद् द्वारा मनोनीत दो चुने-हुये प्रतिनिधि	सदस्य
4. जिला योजना अधिकारी	सदस्य
5. उप निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी	सदस्य
6. जिला बागवानी अधिकारी	सदस्य
7. उप निदेशक, मछली पालन	सदस्य
8. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी	सदस्य
9. उपायुक्त द्वारा मनोनीत एस०एच०जी०/एफ०आई०जी०/सी०आई०जी० के दो प्रतिनिधि	सदस्य
10. वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
11. विख्यात एन०जी०ओ० के उपायुक्त द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि	सदस्य
12. नाबार्ड के डी०डी०एम०	सदस्य
13. लीड बैंक का जिला प्रबन्धक	सदस्य
14. जिला सूचना अधिकारी (एन०आई०सी०)	सदस्य
15. उप कृषि निदेशक	सदस्य सचिव

जिला कृषि योजना इकाई निम्नलिखित कार्य करेगी :—

- 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिये जिले की वर्तमान स्थिति व इसकी विशेष आवश्यकताओं का विश्लेषण करेगी।
- पांच वर्ष की मध्यम समय की अवधि में जिला क्या प्राप्त करना चाहता है तथा इसे प्राप्त करने के लिये क्या कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी, का विश्लेषण करेगी।
- जिला के कार्य क्षेत्र में विस्तृत कृषि योजना तैयार करने के लिए पहले से लागू योजनाओं के साथ-साथ नई योजनाओं के उद्देश्यों को सम्मिलित करके उनका विश्लेषण करेगी।
- वित्तीय सहायता के साथ कार्य योजना तैयार करने के साथ-साथ इसकी निरन्तर समीक्षा करेगी।
- जिला स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भारत निर्माण व पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फण्ड के माध्यम से कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों, जल संसाधनों व ग्रामीण विकास में पर्याप्त वृद्धि के लिये संसाधनों के उचित प्रयोग करने हेतु कृषि विकास के लिये योजना, प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करेगी।

शकुन्तला जाखु,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
कृषि विभाग।

## AGRICULTURE DEPARTMENT

The 2nd March, 2009

**No. 589-Agri. II(1)-2009/2596.**—The Governor of Haryana is pleased to constitute a District Agriculture Planning Unit (DAPU) for discussion of farm problems to find out research and extension gap and for making strategies and its incorporation in the Comprehensive District Agriculture Plan as required under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) with the following composition :—

1. Chairman Zila Parishad	Chairman
2. Deputy Commissioner	Vice-Chairman
3. Two Elected Representative nominated by Zila Parishad	Member
4. District Planning Officer	Member
5. Deputy Director, Animal Husbandry and Dairying	Member
6. District Horticulture Officer	Member
7. Deputy Director Fisheries	Member
8. District Development and Panchayat Officer	Member
9. Two Representative of SHG/FIGs/CIGs (Nominated by Deputy Commissioner)	Member
10. Senior Coordinator, KVK	Member
11. Representative of reputed NGO (Nominated by Deputy Commissioner)	Member
12. DDM of NABARD	Member
13. District Manager of Lead Bank	Member
14. District Information Officer (NIC)	Member
15. Deputy Director of Agriculture	Member Secretary

The District Agriculture Planning Unit shall perform the following functions :—

1. Analysis of the current situation of the District and particularly its needs and potentials to achieve the 4% annual growth in the agricultural sector during the 11th plan.
2. Analysis that what the District will try to achieve over a medium term, of five years and how it intends to achieve it.
3. Preparation of comprehensive District Agriculture Plan mentioning the objectives and analysis of ongoing as well as new schemes and programmes within the purview of the District.
4. Prepare an action plan along with the financial outlay with a provision of continuous updating.
5. Convergence in Planning, management and implementation in agriculture development for making optimum use of resources in the context of quantum jump in the outlays in agriculture and allied sectors, water resources and rural development through RKVY, NFSM, NHM, NREGA, Bharat Nirman and Backward Region Grant Fund (BRGF) at District level.

SHAKUNTALA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana, Agriculture Department.